

अमर नाथ चौधरी

बनाम

ब्रैथवेट और कंपनी लिमिटेड और अन्य

11 जनवरी, 2002

[न्यायाधिपति वी. एन. खरे और न्यायाधिपति अशोक भान]

सेवा कानून: अनुशासनात्मक कार्यवाही-पक्षपात-अनुशासनात्मक आदेश के खिलाफ अपील प्राधिकरण-अपीलीय प्राधिकरण के रूप में भी कार्य करने वाला अनुशासनात्मक प्राधिकरण-आयोजित, पक्षपात के कारण दूषित अपीलीय प्राधिकरण का आदेश-दोहरे कार्य की अनुमति केवल तभी दी जाती है जब कानून के किसी अधिनियम या वैधानिक प्रावधान द्वारा अनुमति दी जाती है-प्रशासनिक कानून-पक्षपात।

प्रतिवादी-कंपनी द्वारा अपीलकर्ता के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू की गई। अनुशासनात्मक प्राधिकारी, जो कंपनी के अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक थे, ने जांच समिति की रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया और अपीलकर्ता को सेवा से हटा दिया। अपीलकर्ता ने कंपनी द्वारा बनाए गए नियमों के तहत उक्त आदेश के खिलाफ निदेशक मंडल के समक्ष अपील की, जिसे एक गैर-स्पष्ट आदेश द्वारा खारिज कर दिया गया। अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक ने बोर्ड की बैठक की अध्यक्षता की और विचार-विमर्श में भाग लिया। अपीलकर्ता ने उक्त आदेश को चुनौती देते हुए रिट याचिका दायर की जिसे एकल न्यायाधीश ने अनुमति दे दी। अपील में डिवीजन बेंच ने एकल न्यायाधीश के आदेश को पलट दिया। इसलिए यह अपील की गई।

अपीलकर्ता ने तर्क दिया कि बोर्ड की बैठक के विचार-विमर्श में अनुशासनात्मक प्राधिकारी की भागीदारी से कानूनी पूर्वाग्रह के कारण अपीलीय प्राधिकारी का आदेश दूषित हो गया था, जिसने उसकी अपील पर फैसला किया था।

प्रतिवादी ने आवश्यकता के सिद्धांत पर भरोसा किया और उस नियम का विरोध किया पूर्वाग्रह के खिलाफ उपलब्ध नहीं है क्योंकि कंपनी द्वारा बनाए गए नियमों के तहत अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक को बोर्ड की बैठक में भाग लेना आवश्यक था। अपील की अनुमति देते हुए,

न्यायालय ने आयोजित किया।

1. जहां एक प्राधिकारी ने पहले कोई निर्णय लिया था, वह अपने ही निर्णय के खिलाफ अपील में बैठने के लिए अयोग्य है, क्योंकि उसने पहले ही मामले पर पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर फैसला कर लिया था, अन्यथा ऐसी अपील को सीज़र से सीज़र के पास अपील और अपील दायर करना कहा जाएगा। यह व्यर्थ का अभ्यास होगा। पूर्वाग्रह के विरुद्ध स्थापित नियम के कारण ऐसा दोहरा कार्य स्वीकार्य नहीं है। ऐसी स्थिति में जहां एक ही प्राधिकारी द्वारा इस तरह के दोहरे कार्य का निर्वहन किया जाता है, जब तक कि किसी कानून या वैधानिक प्रावधान द्वारा इसकी अनुमति नहीं दी जाती है, तो यह पूर्वाग्रह के खिलाफ नियम के विपरीत होगा। [187-जी)

वित्तीय आयुक्त (कराधान) पंजाब और अन्य बनाम हरभजन सिंह, [1996] 9 एससीसी 281, ने भरोसा किया।

2. निष्पक्ष खेल के अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक से मांग की गई जब बोर्ड ने अपीलकर्ता की अपील सुनी और निर्णय लिया तो कंपनी को बोर्ड की बैठक के विचार-विमर्श में भाग नहीं लेना चाहिए था। बोर्ड कंपनी के अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक को बाहर करके बोर्ड/प्रबंधन या कंपनी के किसी भी अधिकारी की एक समिति गठित कर सकता था और पक्षपात के किसी भी आरोप को खत्म करने के लिए अपीलीय शक्ति

सहित अपनी कोई भी शक्ति ऐसी समिति को सौंप सकता था। ऐसे अपीलीय प्राधिकारी के विरुद्ध. वर्तमान मामले में आवश्यकता के सिद्धांत पर निर्भरता पूरी तरह से गलत है। [188-ई]

3. चुनौती के तहत आदेश और निर्णय के साथ-साथ अपीलीय प्राधिकारी द्वारा पारित आदेश को रद्द कर दिया जाता है और मामले को कानून के अनुसार स्पीकिंग ऑर्डर द्वारा अपील पर निर्णय लेने के लिए अपीलीय प्राधिकारी को वापस भेज दिया जाता है। [188-जी]

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार : सिविल अपील संख्या 193/2002

1992 के एफ.एम.ए संख्या 144 में कोलकाता उच्च न्यायालय के निर्णय और आदेश दिनांक 12.5.2000 से।

अपीलार्थी की ओर से पी. पी. राव, सुश्री नंदिनी मुखर्जी और देब प्रसाद मुखर्जी।

डी. पी. रॉय चौधरी और जी. एस. चटर्जी प्रतिवादी के लिए।

न्यायालय का निर्णय न्यायाधिपति वी. एन. खरे द्वारा दिया गया।

अनुमति दी गई।

इसमें अपीलकर्ता भारत सरकार के उपक्रम ब्रेथवेट एंड कंपनी लिमिटेड, कलकता (इसके बाद 'कंपनी' के रूप में संदर्भित) का कर्मचारी था। ऐसा प्रतीत होता है कि अपीलकर्ता द्वारा किए गए कुछ कदाचार कंपनी के संज्ञान में आ गए। परिणाम के साथ, कंपनी ने "अपीलकर्ता के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू करने का निर्णय लिया। परिणामस्वरूप, अपीलकर्ता को एक आरोप-पत्र दिया गया, जिस पर उसने स्पष्टीकरण दिया। इस उद्देश्य से गठित एक जांच समिति ने जांच करने के बाद पाया कि अपीलकर्ता के खिलाफ लगाए गए आरोप साबित हुए। जांच समिति ने तदनुसार

अपनी रिपोर्ट अनुशासनात्मक प्राधिकारी को सौंप दी। अनुशासनात्मक प्राधिकारी, जो कंपनी के तत्कालीन अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक थे, ने जांच समिति द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया और उन्होंने दिनांक 13.2.84 के आदेश द्वारा अपीलकर्ता को सेवा से हटा दिया।

कंपनी द्वारा बनाए गए नियमों के तहत अनुशासनात्मक प्राधिकारी के किसी आदेश के खिलाफ अपील कंपनी के निदेशक मंडल (इसके बाद 'बोर्ड' के रूप में संदर्भित) के समक्ष की जा सकती है। अपीलकर्ता ने बोर्ड के समक्ष उसे सेवा से हटाने के आदेश के खिलाफ अपील दायर की। यह विवादित नहीं है कि श्री एस. कृष्णास्वामी, जो उस समय कंपनी के अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक थे और जिन्होंने अनुशासनात्मक प्राधिकारी के रूप में अपीलकर्ता को सेवा से हटा दिया था, ने बोर्ड की बैठक की अध्यक्षता की और विचार-विमर्श में भाग लिया। बोर्ड ने आदेश दिनांक 31.8.84 द्वारा, अपीलकर्ता द्वारा दायर अपील को एक गैर-स्पष्ट आदेश द्वारा खारिज कर दिया। व्यथित होकर, अपीलकर्ता ने कलकत्ता उच्च न्यायालय के समक्ष भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत एक रिट याचिका दायर की। उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश ने कार्यवाही में दोष पाए जाने के बाद अपीलकर्ता के खिलाफ पारित निष्कासन आदेश को रद्द कर दिया। कंपनी ने उच्च न्यायालय की खंडपीठ के समक्ष लेटर्स पेटेंट अपील दायर की। डिवीजन बेंच ने विद्वान एकल न्यायाधीश के आदेश और फैसले को गलत पाया और मामले के मद्देनजर, विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश को रद्द कर दिया गया और अपीलकर्ता द्वारा दायर रिट याचिका खारिज कर दी गई। यह उच्च न्यायालय के उक्त निर्णय और आदेश के विरुद्ध है, अपीलकर्ता ने यह अपील दायर की है।

इस न्यायालय ने विशेष अनुमति याचिका, जिससे वर्तमान अपील उत्पन्न हुई है, पर विचार करते हुए निम्नलिखित आदेश पारित किया:

"नोटिस केवल इस प्रश्न तक सीमित रखें कि मामले को अपीलीय प्राधिकारी को क्यों नहीं भेजा जा सकता है।"

अपीलकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ वकील श्री पी.पी.राव द्वारा उठाए गए तर्कों में से एक यह है कि हटाने का आदेश अनुशासनात्मक प्राधिकारी - श्री एस.कृष्णास्वामी, जो उस समय अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक थे, द्वारा पारित किया गया था। कंपनी को बोर्ड की बैठक की अध्यक्षता करने और विचार-विमर्श में भाग लेने के लिए अयोग्य ठहराया गया था, जिसने अपील सुनी और खारिज कर दी और इसलिए, अपीलीय प्राधिकरण का आदेश कानूनी पूर्वाग्रह के कारण दूषित हो गया था। हमें तर्क में दम नजर आता है. यह विवादित नहीं है कि श्री एस.कृष्णास्वामी उस समय कंपनी के अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक थे। यह भी विवादित नहीं है कि श्री कृष्णास्वामी भी अनुशासनात्मक प्राधिकारी थे जिन्होंने अपीलकर्ता के खिलाफ निष्कासन का आदेश पारित किया था। इसलिए, सवाल उठता है कि क्या अपीलकर्ता द्वारा दायर अपील पर निर्णय लेते समय अनुशासनात्मक प्राधिकारी की भागीदारी के कारण बोर्ड की कार्यवाही दूषित हो गई थी।

प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों में से एक यह है कि कोई भी व्यक्ति अपने मामले में न्यायाधीश नहीं होगा या निर्णय लेने वाला प्राधिकारी निष्पक्ष होना चाहिए और किसी भी प्रकार के पूर्वाग्रह के बिना कार्य करना चाहिए। पूर्वाग्रह के खिलाफ उक्त नियम की उत्पत्ति 'डेबेट एसे ज्यूडेक्स इन प्रोप्रिया कॉसा' नामक कहावत से हुई है, जो इस सिद्धांत पर आधारित है कि न्याय न केवल किया जाना चाहिए बल्कि स्पष्ट रूप से होते हुए दिखना भी चाहिए। यह तभी संभव हो सकता है जब कोई न्यायाधीश या निर्णय लेने वाला प्राधिकारी मामले का निर्णय निष्पक्षता से और किसी भी प्रकार के पूर्वाग्रह के बिना करे। पूर्वाग्रह विभिन्न प्रकार और स्वरूप का हो सकता है। यह आर्थिक, व्यक्तिगत हो सकता है या विषय-वस्तु आदि के बारे में पूर्वाग्रह हो सकता है। वर्तमान मामले में,

हम पूर्वाग्रह के किसी भी पूर्वोक्त रूप से चिंतित नहीं हैं। वर्तमान मामले में हम इस बात से चिंतित हैं कि क्या कोई प्राधिकारी अनुशासनात्मक प्राधिकारी की क्षमता में पारित अपने ही आदेश के खिलाफ अपील में बैठ सकता है। वित्तीय आयुक्त (कराधान) पंजाब और अन्य बनाम हरभजन सिंह, [1996] 9 सेकंड 281 में, यह माना गया कि निपटान अधिकारी को अपीलीय प्राधिकारी के रूप में उसके द्वारा पारित आदेश पर विचार करने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है। वर्तमान मामले में, बोर्ड के समक्ष अपील का विषय यह था कि क्या अनुशासनात्मक प्राधिकारी द्वारा पारित निष्कासन आदेश कानून के अनुरूप था। यह विवादित नहीं है कि कंपनी के तत्कालीन अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक श्री एस. कृष्णास्वामी ने एक अनुशासनात्मक प्राधिकारी के साथ-साथ एक अपीलीय प्राधिकारी के रूप में कार्य किया जब उन्होंने अपील पर निर्णय लेते समय बोर्ड की बैठक की अध्यक्षता की और विचार-विमर्श में भाग लिया। अपीलकर्ता का. पूर्वाग्रह के विरुद्ध स्थापित नियम के कारण ऐसा दोहरा कार्य स्वीकार्य नहीं है। ऐसी स्थिति में जहां इस तरह के दोहरे कार्य का निर्वहन एक और एक ही प्राधिकारी द्वारा किया जाता है जब तक कि कानून या वैधानिक प्रावधान के किसी अधिनियम द्वारा अनुमति नहीं दी जाती है, यह पूर्वाग्रह के खिलाफ नियम के विपरीत होगा। जहां एक प्राधिकारी ने पहले कोई निर्णय लिया था, वह अपने ही फैसले के खिलाफ अपील में बैठने के लिए अयोग्य है, क्योंकि उसने पहले ही मामले पर पूर्वाग्रह से निर्णय ले लिया था अन्यथा ऐसी अपील को सीज़र से सीज़र के लिए अपील कहा जाएगा और अपील दायर करना एक अभ्यास होगा। वर्तमान मामले में, निष्पक्ष खेल की मांग है कि कंपनी के तत्कालीन अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक श्री कृष्णास्वामी को बोर्ड की बैठक के विचार-विमर्श में भाग नहीं लेना चाहिए जब बोर्ड ने अपीलकर्ता की अपील सुनी और निर्णय लिया।

हालाँकि, प्रतिवादी की ओर से उपस्थित विद्वान वकील ने अपने तर्क के समर्थन में "आवश्यकता के सिद्धांत" का सहारा लिया। उन्होंने तर्क दिया कि पूर्वाग्रह के खिलाफ नियम उपलब्ध नहीं है, जब कंपनी द्वारा बनाए गए नियमों के तहत, अनुशासनात्मक

प्राधिकारी जो कंपनी के अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक थे, को बोर्ड की बैठक की अध्यक्षता करने की आवश्यकता थी और इसलिए, तत्कालीन कंपनी के अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक को बोर्ड की बैठक की अध्यक्षता करने और उसमें भाग लेने के लिए अयोग्य नहीं ठहराया गया, जिसने अपीलकर्ता की अपील को खारिज कर दिया। हमें इस तर्क में कोई दम नजर नहीं आता। कंपनी के आचरण, अनुशासन और अपील नियमों के नियम 3 (डी) (संक्षेप में 'सीडीएआर') 'बोर्ड' को निम्नलिखित शब्दों में परिभाषित करता है:

"बोर्ड का मतलब कंपनी के मालिकों से है और इसमें संबंध भी शामिल है, बोर्ड/प्रबंधन की किसी समिति या कंपनी के किसी अधिकारी, जिसे बोर्ड अपनी कोई शक्ति सौंपता है, उसकी शक्तियों का प्रयोग करना।"

अभिव्यक्ति 'बोर्ड' की उपरोक्त परिभाषा के मद्देनजर, बोर्ड कंपनी के अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक को छोड़कर बोर्ड/प्रबंधन या कंपनी के किसी भी अधिकारी की एक समिति का गठन कर सकता था और अपनी कोई भी शक्ति सौंप सकता था, जिसमें शामिल हैं ऐसी समिति को ऐसे अपीलीय प्राधिकारी के खिलाफ पूर्वाग्रह के किसी भी आरोप को खत्म करने की अपीलीय शक्ति। इसलिए, यह तर्क देना सही नहीं है कि वर्तमान मामले में 'आवश्यकता के सिद्धांत' के मद्देनजर पूर्वाग्रह के खिलाफ नियम उपलब्ध नहीं है। इसलिए, हमारा विचार है कि वर्तमान मामले में आवश्यकता के सिद्धांत पर निर्भरता पूरी तरह से गलत है।

यहां पहले बताए गए कारणों से, हम पाते हैं कि अपील सफल होने लायक है। तदनुसार, चुनौती के तहत आदेश और निर्णय के साथ-साथ अपीलीय प्राधिकारी द्वारा पारित आदेश को रद्द कर दिया जाता है और कानून के अनुसार, स्पीकिंग ऑर्डर द्वारा अपील पर निर्णय लेने के लिए मामला अपीलीय प्राधिकारी को वापस भेज दिया जाता है। मामले से अलग होने से पहले, हम यह निर्देश देते हैं कि कंपनी अपीलकर्ता को

उसके सुपरएनुएशन पर भुगतान किए गए किसी भी पैसे की वसूली के लिए कोई कदम नहीं उठाएगी, जब तक कि मामला उचित अपीलीय प्राधिकारी द्वारा अंतिम रूप से तय नहीं हो जाता।

अपील स्वीकार की जाती है. लागत के रूप में कोई आदेश नहीं किया जाएगा।

ए के टी

अपील की अनुमति दी जाती है।



यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक अधिवक्ता निशा पालीवाल द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।